

# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

# उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, बृहस्पतिवार, 22 मई, 2025 ई0 (ज्येष्ठ 01, 1947 शक संवत्)

# कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या-463/दस-लाइसेंस-58/देशी शराब थोक-नियमावली/2024-2025 प्रयागराज, दिनांक 22 मई, 2025 ई0

## अधिसूचना

#### सा0प0नि0-36

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24 और 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त की अधिसूचना संख्या 31276/दस-लाइसेंस-58/2002-2003, दिनांक 26 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 को संशोधित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

#### उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन)

#### (सत्रहवॉ संशोधन) नियमावली, 2025

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) (सत्रहवॉ संशोधन) नियमावली, 2024 कही जायेगी।
  - (2) यह दिनांक 1 अप्रैल, 2024 से प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी।

2. नियम-4 का संशोधन– उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी **शराब** की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002, में नीचे स्तम्भ-**एक** में, दिये गये **विद्यमान** नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ-**दो** में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

## स्तम्भ-**एक** विद्यमान नियम

#### 4-लाइसेंस की स्वीकृति

- (1)(क)देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंस, आबकारी आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी, जो इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस की अपेक्षित धनराशि से अन्यून कुल मालियत के ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकन द्वारा निर्गत सम्पत्ति का स्वामित्व प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने तथा लाइसेंस फीस के भुगतान और अधिमानतः ई-भुगतान प्लेटफार्म के माध्यम से और आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत प्रतिभूति धनराशि/ सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से प्रत्येक जिले में प्रपत्र सी0एल0-2 में आवेदक के आवेदन करने पर प्रदान किया जायेगा।
- (ख) प्रपत्र सी0एल0-2 में देशी शराब की थोक बिक्री हेतु लाइसेंस का नवीकरण राज्य सरकार द्वारा विहित निबन्धन एवं शर्तों के अध्यधीन सम्बन्धित जोन के संयुक्त आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त द्वारा किया जा सकेगा।

#### स्तम्भ-दो

#### एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

4-लाइसेंस की स्वीकृति

- (1)(क)देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंस, आबकारी आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी,जो इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस की अपेक्षित धनराशि से अन्यून कुल मालियत के ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति का स्वामित्व प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने तथा लाइसेंस फीस के भुगतान और अधिमानतः ई-भुगतान प्लेटफार्म के माध्यम से और आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत प्रतिभूति धनराशि/ सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से प्रत्येक जिले में प्रपत्र सी0एल0-2 में आवेदक के आवेदन करने पर प्रदान किया जायेगा।
- (ख) प्रपत्र सी0एल0-2 में देशी शराब की थोक बिक्री हेतु लाइसेंस का नवीकरण, राज्य सरकार द्वारा विहित निबन्धन एवं शर्तों के अध्यधीन सम्बन्धित जोन के संयुक्त आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त द्वारा किया जा सकेगा।

लाइसेंसधारी को इस आशय का रु. 10/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत शपथ पत्र भी देना होगा कि:-

- (एक) वह सुसंगत वर्ष हेतु विहित समस्त देय संदाय करने को तैयार है तथा उसके लाइसेंस के वर्तमान परिसर और स्थान की चौहद्दी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
- (दो) वह उक्त थोक लाइसेंस के लिये अपेक्षित सभी अर्हतायें रखता है; और
- (तीन) वह वर्तमान लाइसेंस को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे गम्भीर अनियमितता अथवा लाइसेंस निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो।

स्तम्भ- <b>एक</b>	स्तम्भ-दो
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

लाइसेंस की शर्तों का पालन न करने अथवा शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में नवीकरण निरस्त कर दिया जाएगा तथा सुसंगत वर्ष में लाइसेंस हेतु जमा प्रतिभूति धनराशि का 50 प्रतिशत एवं आगामी वर्ष हेतु जमा नवीकरण एवं लाइसेंस फीस, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी।

आगामी वर्ष के लिए नवीकरण हेतु इच्छुक थोक लाइसेंस के लाइसेंसधारी नवीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे, विहित शपथ पत्र एवं संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे तथा नवीकरण फीस की धनराशि को ऑनलाइन जमा करेंगे। आवेदन पत्र प्राप्त होने के दिनांक से 07 कार्य दिवस के भीतर लाइसेंस प्राधिकारी अथवा प्राधिकृत प्राधिकारी नवीकरण पर विनिश्चय करेगा और सम्बंधित इच्छुक लाइसेंसधारी को 03 कार्यदिवस के भीतर सम्बंधित लाइसेंस हेतु विहित लाइसेंस फीस धनराशि जमा करने का निदेश देगा। प्रतिभूति धनराशि में अंतर लाइसेंसधारी द्वारा नवीकरण स्वीकृत किये जाने के दिनांक से 15 दिन के भीतर जमा किया जा सकेगा।

यदि प्रतिभूति का अंतर विहित अविध के भीतर नहीं जमा किया जाता है, तो रु.2000/- प्रति दिवस का जुर्माना उद्ग्रहीत किया जाएगा। जुर्माना सहित मात्र 15 दिवस की अविध प्रतिभूति धनराशि का अंतर जमा करने हेतु अनुज्ञात होगी और यदि इस अतिरिक्त अविध के भीतर भी प्रतिभूति धनराशि का अंतर जमा नहीं किया जाता है तो नवीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

यदि लाइसेंसधारी उपरोक्त विहित प्रक्रिया का पालन नहीं करता है अथवा प्रतिभूति धनराशि का अंतर अनुज्ञात अविध के भीतर जमा नहीं करता है अथवा अपने द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का अनुपालन नहीं करता है, तो उसका नवींकरण निरस्त कर दिया जायेगा और सुसंगत वर्ष हेतु उसकी प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं आगामी वर्ष के लिए नवींकरण फीस राज्य सरकार के पक्ष में समपहत कर ली जायेगी।

स्तम	भ-ए	क्र

#### विद्यमान नियम

नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र/बैंक गारंटी के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय और गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा किसी आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि विधिमान्य एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है. प्रतिग्राह्य होंगे।

(2) लाइसेंसधारी को, किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस अन्तरित करने या शिकमी करने की अनुमति न होगी।

#### स्तम्भ-दो

#### एतदुद्वारा प्रतिस्थापित नियम

नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र/बैंक गारंटी के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय और गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा किसी आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि विधिमान्य एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होंगे।

(2) लाइसेंसधारी को, किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस अन्तरित करने या शिकमी करने की अनुमति न होगी।

आजा से,

डा० आदर्श सिंह, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

#### OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

No. 393/10-License-222/Composite Shop/2025-26

Prayagraj, Dated: May 16, 2025

#### **NOTIFICATION**

In exercise of the powers under sections 24 and 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. 4 of 1910) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no.1 of 1904), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government, hereby makes the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Excise (Settlement of License for Wholesale of Country Liquor) Rules, 2002 published vide Excise Commissioner Notification No. 31276/X-Licence-58/2002-2003/dated March 26, 2002:—

# THE UTTAR PRADESH EXCISE (SETTLEMENT OF LICENCES FOR WHOLESALE OF COUNTRY LIQUOR)(SEVENTEENTH AMENDMENT) RULES, 2025

- 1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise (Settlement of licences for Wholesale of Country Liquor) (Seventeenth Amendment) Rules, 2024.
  - (2) They shall be deemed to have come into force with effect from 01st April, 2024.
- 2. In the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licences for Wholesale of Country Liquor) Rules, 2002, for the existing rule 4 setout in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:—

#### Column-I

(Existing rule)

#### 4. Grant of licence

- (1)(a) The license for wholesale of country liquor shall be granted on submission of solvency certificate or certificate of owned property issued by authorized Income Tax Valuer bearing net worth not less than the requisite amount of license fee and payment of license fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through Fixed Deposit Receipt pledged in favour of Excise commissioner Uttar Pradesh, or through e-payment in accordance with the provisions of these rules, in every district in form CL-2 on application of applicant.
- (b) The license for wholesale of Country Liquor in Form CL-2 may be renewed by the Deputy Excise Commissioner of the concerned charge with the prior approval of the joint Excise commissioner of the concerned zone subject to the terms and conditions prescribed by the State Government.

#### Column-II

(Rule as hereby substituted)

#### 4. Grant of licence

- (1)(a) The license for wholesale of country liquor shall be granted on submission of solvency certificate or certificate of owned property issued by authorized Income Tax Valuer bearing net worth not less than the requisite amount of license fee and payment of license fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through Fixed Deposit Receipt pledged in favour of Excise commissioner Uttar Pradesh, or through e-payment in accordance with the provisions of these rules, in every district in form CL-2 on application of applicant.
- (b) The license for wholesale of Country Liquor in Form CL-2 may be renewed by the Deputy Excise Commissioner of the concerned charge with the prior approval of the joint Excise commissioner of the concerned zone subject to the terms and conditions prescribed by the State Government.

The licencee will also have to give a notarized affidavit on a non-judicial stamp paper of Rs.10/- to the effect that:-

- (i) he is ready to pay all the dues prescribed for the relevant year and no change has been made in the boundaries of the current premises and place of his licence;
- (ii) he has all the qualifications required for the said wholesale licence; and that
- (iii) he will operate the current license with full devotion and honesty and will not do anything that may lead to serious irregularities or cancellation of licence.

In case of not following the conditions of the licence or acting contrary to the facts mentioned in the affidavit, the renewal will be cancelled and 50 percent of the security amount deposited in relevant year for the licence and the renewal and licence fee deposited for the next year will be forfeited in favor of the State Government.

Column-1	I

#### (Existing rule)

#### Column-II

(Rule as hereby substituted)

The licencees of wholesale licenses willing to renew for the next year shall submit the application online, upload renewal prescribed affidavit and the No Objection Certificate issued by the concerned District Excise Officer and deposit the renewal fee amount online. Within 07 working days from the date of receipt of the application, the licensing authority or the authorized authority shall take a decision on renewal and direct the concerned interested licencee to deposit the prescribed license fee amount for the concerned license within 03 working days. The difference in the security amount may be deposited by the licencee within 15 days from the date of approval of renewal.

If the difference in the security amount is not deposited within the prescribed period, a fine of Rs.2000/- per day shall be levied. Only a period of 15 days including the fine shall be allowed for depositing the difference in the security amount and if the difference in the security amount is not deposited even within this additional period, the renewal shall be cancelled.

If the licencee does not follow the procedure prescribed above or does not deposit the difference in the security amount within the allowed time or does not comply with the affidavit submitted by him, his renewal will be cancelled and 50 percent of his security for the relevant year and the renewal fee for the next year will be forfeited to the State Government.

#### Column-I

#### (Existing rule)

In case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate/Bank Guarantee shall be acceptable till it is not refunded and the solvency certificate or certificate of owned property issued by an income tax valuer during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount.

(2) The Licensee shall not be permitted to transfer or sublet the licence to any other person.

#### Column-II

(Rule as hereby substituted)

In case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate/Bank Guarantee shall be acceptable till it is not refunded and the solvency certificate or certificate of owned property issued by an income tax valuer during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount.

(2) The Licensee shall not be permitted to transfer or sublet the licence to any other person.

By order,

DR. ADARSH SINGH, Excise Commissioner, Uttar Pradesh.